



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-04122024-259154
CG-MH-E-04122024-259154

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 968]
No. 968]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 4, 2024/अग्रहायण 13, 1946
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 4, 2024/AGRAHAYANA 13, 1946

बैंक ऑफ महाराष्ट्र
अधिसूचना

पुणे, 4 दिसम्बर, 2024

फा. सं.: एएक्स1/एसटी/ओएसआर/119/2024-25.—बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 12 की उप धारा (2) के साथ पठित धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बैंक ऑफ महाराष्ट्र का निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श के बाद और केंद्र सरकार की पिछली मंजूरी के साथ, वित्तीय सेवा विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र क्रमांक 4/2/2/2015-आईआर, दिनांक 18 दिसंबर, 2020 के अनुसरण में किए गए या किए जाने से हटाए गए कार्यों को छोड़कर 1 नवंबर 2017 से आधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि तक, एतद्वारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

- (1) इन विनियमों को बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकता है।
(2) ये आधिकारिक राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होंगे।
- बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 (इसके उपरांत एतद्वारा उक्त विनियमों के रूप में संदर्भित) में, विनियम 3 में, खंड (एफ) के लिए, निम्नलिखित खंड को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् —

चिकित्सा सुविधाओं के प्रयोजन तथा छुट्टी किराया रियायत के प्रयोजन के लिए (एफ) "परिवार" का अर्थ है अधिकारी

की पत्नी/ पति, पूर्ण रूप से आश्रित अविवाहित बच्चे (सौतेले बच्चों और कानूनी रूप से गोद लिए गए बच्चों सहित), चालीस प्रतिशत या अधिक विकलांगता के साथ शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग पूरी तरह से आश्रित भाई या बहन, विधवा बेटियां और आश्रित तलाकशुदा या परित्यक्त बेटियां, बहनें जिनमें अविवाहित या तलाकशुदा या परित्यक्त या पति से अलग या विधवा बहनें शामिल हैं और पूरी तरह से अधिकारी पर निर्भर माता-पिता शामिल हो सकते हैं।

स्पष्टीकरण; —

(i) "पूर्ण रूप से आश्रित" का अर्थ परिवार के ऐसे सदस्य से होगा जिसकी आय **रु.12,000 प्रति माह** से अधिक नहीं है। यदि माता-पिता में से किसी की आय **रु.12,000 प्रति माह** से अधिक है या माता-पिता दोनों की कुल आय यदि **रु.12,000 प्रति माह** से अधिक है तो माता-पिता दोनों को अधिकारी पर पूर्ण रूप से आश्रित नहीं माना जाएगा।

(ii) एक विवाहित महिला अधिकारी अपने प्राकृतिक माता-पिता या सास-ससुर को परिवार की परिभाषा में शामिल कर सकती है, लेकिन दोनों को नहीं, बशर्ते कि माता-पिता या सास-ससुर पूरी तरह से उस पर आश्रित हों।

नोट 1: चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति योजना के उद्देश्य से, सभी अधिकारियों, अर्थात् पुरुष या महिला के लिए आश्रित माता-पिता या सास-ससुर में से किन्हीं दो को कवर किया जाएगा। अधिकारी के पास आश्रितों में से किसी एक या दोनों को प्रतिस्थापित करने का विकल्प होगा।

नोट 2: किसी अधिकारी के शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों को, उनकी आयु या वैवाहिक स्थिति पर ध्यान दिए बिना, आय मानदंड के अधीन, आश्रित के रूप में परिभाषित किया जाएगा।

(ii) खंड (i) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

“(i) “प्रबंध निदेशक” का तात्पर्य बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी से है;”.

3. उक्त विनियमों के विनियम 4 में,-

(i) उप-विनियम (6) में, स्पष्टीकरण हटा दिया जाएगा;

(ii) उप-विनियम (7) और (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्: -

(7) 1 नवंबर, 2017 से प्रभावी प्रत्येक श्रेणी के लिए निर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे: —

(क) शीर्ष कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान VII = ₹116120 – 3220/4 – 129000

वेतनमान VI = ₹ 104240 – 2970/4 – 116120

(ख) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

वेतनमान IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890– 2500/2 – 89890

(ग) मध्यम प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान III = ₹ 63840-1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

वेतनमान II = ₹ 48170–1740/1 - 49910 -1990/10 – 69810

(घ) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी

वेतनमान I = ₹ 36000-1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

स्पष्टीकरण—प्रत्येक अधिकारी, जो 31 अक्टूबर, 2017 को लागू वेतनमानों द्वारा शासित है, को चरण-दर-चरण आधार पर 1 नवंबर, 2017 को इस उप-विनियम के अनुसार निर्धारित वेतनमान में अर्थात् संबंधित वेतनमानों में पहले चरण से आगे संबंधित चरणों में फिट किया जाएगा और वेतन वृद्धि अन्यथा प्रावधान न होने पर हमेशा की तरह वर्षगांठ की तारीख पर दी जाएगी।

(8) उप-विनियम (1), (2), (3), (4), (5), (6) और (7) में ऐसा कुछ भी नहीं माना जाएगा कि बैंक के लिए हर समय इन सभी श्रेणियों में सेवारत अधिकारी आवश्यक हैं।

(9) (क) 1 नवंबर, 2012 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता दिया जाएगा :—

वेतनमान I-III = मूल वेतन का 7.75% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV-V = मूल वेतन का 10% + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI-VII = मूल वेतन का 11%+ उस पर लागू महंगाई भत्ता

(ख) 1 नवंबर, 2017 से अधिकारियों को निम्नानुसार विशेष भत्ता दिया :—

वेतनमान I – III - मूल वेतन का 16.40 % + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान IV – V - मूल वेतन का 19 % + उस पर लागू महंगाई भत्ता

वेतनमान VI – VII - मूल वेतन का 20 % + उस पर लागू महंगाई भत्ता

नोट: उप-विनियम (9) के खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट विशेष भत्ता और उस पर लागू महंगाई भत्ते को नई पेंशन योजना, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन जैसे सेवानिवृत्ति लाभों के लिए शामिल नहीं किया जाएगा।”

4. उक्त विनियमों के विनियम 5 में—

(i) उप-विनियम (1) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् -

"(1) विनियम 4 के उप-विनियम (7) के प्रावधानों के अधीन, 1 नवंबर, 2017 के पहले दिन को और उस दिन से, वेतन वृद्धि निम्नलिखित के अधीन दी जाएगी, अर्थात् :-

(क) विनियम 4 के उप-विनियम (7) में निर्धारित वेतनमान में निर्दिष्ट वेतन वृद्धि, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अधीन, वार्षिक आधार पर उपार्जित होगी और उस महीने के पहले दिन दी जाएगी, जिसमें यह देय है;

(ख) अपने संबंधित वेतनमान में अधिकतम स्तर तक पहुंचने के एक वर्ष बाद, वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अगले उच्च वेतनमान में अवरुद्ध वेतन वृद्धि सहित आगे की वेतन वृद्धि उनके क्षमता मानक को पार करने के अधीन नीचे खंड (सी) में निर्दिष्ट अनुसार ही प्रदान की जाएगी;

(ग) कनिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान I में अधिकारी, जो उच्च वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में अंतरित हो गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों हेतु पांच अवरुद्ध वेतन वृद्धि के पात्र होंगे, जिनमें से पहले दो रु.1990/- प्रत्येक और अगले तीन रु.2220/- प्रत्येक होंगे।

बशर्ते कि अधिकारी चौथी वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(घ) मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान II में अधिकारी, जो उच्च वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के बाद खंड (बी) के संदर्भ में मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अंतरित हो गए हैं, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए रु. 2220/- प्रत्येक की पांच अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि अधिकारी चौथी वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2017 को, जो भी बाद में हो, पांचवीं वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(ड.) मूलतः मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में अधिकारी, अर्थात् वे जो मध्यम प्रबंधन श्रेणी वेतनमान III में भर्ती किए गए हैं या पदोन्नत हुए हैं, वे छह अवरुद्ध वेतन वृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से प्रथम चार अवरुद्ध वेतन वृद्धियां प्रत्येक रु.2220/-, अधिकतम तक पहुंचने के बाद पूरी की गई प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए प्रदान की जाएंगी और अगली दो अवरुद्ध वेतन वृद्धियां प्रत्येक रु.2500/-, चौथी अवरुद्ध वेतन वृद्धि प्राप्त करने के बाद पूरी की गई प्रत्येक दो वर्ष की सेवा के लिए प्रदान की जाएंगी:

बशर्ते कि पांचवीं वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर, 2017 को, जो भी बाद में हो, छठी वेतनवृद्धि जारी की जाएगी;

(च) वरिष्ठ प्रबंधक श्रेणी वेतनमान IV के अधिकारी, वेतनमान की अधिकतम सीमा तक पहुंचने के बाद, सेवा के प्रत्येक दो पूर्ण वर्षों के लिए दो अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे, जिनमें से पहली अवरुद्ध वेतनवृद्धि रु.2500/- की होगी और दूसरी अवरुद्ध वेतनवृद्धि रु.2730/- की होगी:

बशर्ते कि अधिकारी प्रथम अवरुद्ध वेतनवृद्धि जारी होने के दो वर्ष पश्चात् अथवा 1 नवम्बर, 2017 को, जो भी बाद में हो, द्वितीय अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होगा;

(छ) 1 नवंबर, 2017 को बैंक में अपनी सेवा के दौरान स्केल I से स्केल IV तक के अधिकारी द्वारा प्राप्त की गई अवरुद्ध वेतनवृद्धि को, इसके पूर्व निर्धारित आवधिकता के अनुसार, उनकी अधिकतम सीमा तक पहुंचने की तिथि से तीन वर्ष की आवधिकता से दो वर्ष की आवधिकता में पुनः समायोजित किया जाएगा और अधिकारी संशोधित आवधिकता के अनुसार 1 नवंबर, 2017 से अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए आनुमानिक रूप से पात्र होंगे, जो सेवानिवृत्ति लाभ के लिए अर्हता प्राप्त करेंगे:

बशर्ते कि अवरुद्ध वेतनवृद्धि की ऐसी संशोधित और पुनः समायोजित आवधिकता के कारण मौद्रिक लाभ 1 नवंबर, 2020 या पात्रता की वास्तविक तिथि, जो भी बाद में हो, से देय होगा:

(ज) वरिष्ठ प्रबंधन श्रेणी वेतनमान V में अधिकारी अधिकतम वेतनमान तक पहुंचने के दो वर्ष बाद या 1 नवंबर 2020 को, जो भी बाद में हो, रु.2970/- की एक अवरुद्ध वेतनवृद्धि के लिए पात्र होंगे:

बशर्ते कि ऐसी वेतनवृद्धि उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जो पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है।

स्पष्टीकरण:-इस उप-विनियम के अंतर्गत अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि प्रदान करना पदोन्नति नहीं माना जाएगा और अधिकारियों के विशेषाधिकार, सुविधाएं, कर्तव्य और जिम्मेदारियां उनके मूल पद के अनुसार जारी रहेंगी।"

(ii) उप-विनियम (2) में, स्पष्टीकरण में, खंड (छ) के पश्चात् और नोट से पहले, निम्नलिखित खंड शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

(एच) 1 नवंबर, 2017 से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की मात्रा नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार संशोधित होगी:-

तालिका

जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के जूनियर एसोसिएट या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट पार्ट I परीक्षा उत्तीर्ण की हो।	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.1020 प्रति माह।
जिन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के सर्टिफाइड एसोसिएट के दोनों भागों को उत्तीर्ण किया हो।	(i) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद रु.1020 प्रति माह। (ii) वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष बाद रु.2550 प्रति माह:

बशर्ते कि वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के बाद भारतीय बैंकर्स संस्थान के जूनियर एसोसिएट या भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट (दोनों में से कोई एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त करने वाले अधिकारी को ऐसी योग्यता प्राप्त करने के दिनांक से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त प्रदान की जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की बाद की किस्तों का जारी करना ऐसी व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त को जारी करने के दिनांक के संदर्भ में होगी।"

(iii) उप-विनियम (3) में, -

(क) खंड (च) में, तालिका के पश्चात, नोट (i) से (vi) को हटा दिया जाएगा:

(ख) खंड (च) के पश्चात, निम्नलिखित खंड प्रविष्ट जाएगा, अर्थात्:—

“(छ) 1 नवंबर, 2017 से, अन्य बातें समान होने पर, मकान किराया भत्ते के साथ नियत वैयक्तिक वेतन निम्नलिखित दरों पर होगा और सेवा की पूरी अवधि के लिए स्थिर रहेगा:—

तालिका

क्र.	वेतनवृद्धि घटक (रु.)	1 नवंबर, 2017 को वेतनवृद्धि घटकों पर महंगाई भत्ता (रु.)	जहां बैंक की सुविधा उपलब्ध है वहां देय कुल नियत व्यक्तिगत वेतन (रु.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1990	53	2043
2.	2220	59	2279
3.	2500	66	2566
4.	2730	73	2803
5.	2970	79	3049
6.	3220	86	3306

नोट:

(i) इस उप-विनियम के खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) और (जी) में तालिकाओं के कॉलम (3) के अंतर्गत दर्शाया गया निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) आवास किराया भत्ता हेतु पात्र अधिकारियों के लिए निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन, कॉलम (1) और (2) के अंतर्गत निर्दिष्ट कुल राशि और संबंधित अधिकारी द्वारा लिया गया आवास किराया भत्ता (एचआरए) होगा जब

विनियम 4 के उप-विनियम (2), (3), (4), (5), (6) और (7) में निर्दिष्ट प्रासंगिक वेतनमान की अंतिम वेतन वृद्धि अर्जित की जाती हो।

(iii) केवल वही अधिकारी जो 1 नवंबर, 1993 को या उससे पहले बैंक की सेवा में है, वे अपने वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष उपरांत निश्चित वैयक्तिक वेतन के लिए पात्र होंगे।

(iv) 1 नवंबर, 1999 को और उसके बाद से, निश्चित वैयक्तिक वेतन जारी करने के कारण उप-विनियम (2) के अंतर्गत स्पष्टीकरण (सी) के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने की अनुसूची तालिका में कोई परिवर्तन नहीं होगा:

बशर्ते कि जहां व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, जो पहले के प्रावधानों के कारण एक वर्ष के लिए अंतरित कर दी गई है और 1 नवंबर, 1999 को या उसके बाद जारी किए जाने के लिए निर्धारित है, वह अधिकारी को उस दिनांक को और उस दिनांक से तथा व्यावसायिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त, यदि कोई हो, 1 नवंबर, 2000 को जारी की जाएगी।

(v) निश्चित वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन का वेतनवृद्धि घटक अधिवर्षिता लाभों के लिए मान्य होगा।

(vi) कोई अधिकारी जिसने इस उप-विनियम के खंड (ए) के अनुसार अग्रिम वेतन वृद्धि अर्जित की है, उसे वेतनमान के अधिकतम स्तर तक पहुंचने के एक वर्ष के उपरांत उपर्युक्त खंड (बी), (सी), (डी), (ई), (एफ) या (जी) में उल्लिखित 'निश्चित' वैयक्तिक भत्ता या निश्चित वैयक्तिक वेतन प्राप्त होगा।

5. उक्त विनियमों के विनियम 20 में, उप-विनियम (1) में, खंड (ग) में, शब्द "अध्यक्ष और" को हटा दिया जाएगा।

6. उक्त विनियमों के विनियम 21 में, -

(क) उप-विनियम (6) में, खंड (बी) में स्पष्टीकरण में, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(एफ) और (जी)" के स्थान पर, कोष्ठक, अक्षर और शब्द "(एफ), (जी) और (एच)" प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(ख) उप-विनियम (6) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(7) 1 नवम्बर, 2017 को और उसके बाद से अखिल भारतीय औसत कर्मकार वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960=100 के त्रैमासिक औसत में 6352 अंकों से अधिक प्रत्येक चार अंकों की वृद्धि या गिरावट के लिए वेतन के 0.07% पर महंगाई भत्ता देय होगा।"

7. उक्त विनियम के विनियम 22 में, उप-विनियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(1) 1 नवम्बर, 2017 को और उसके बाद से,—

(क) जहां किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गई है, वहां उसको वेतनमान के पहले चरण, जिसमें वह पदस्थ है, में मूल वेतन के 0.50 प्रतिशत के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो, उससे वसूल किया जाएगा;

(ख) जहां अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की गई है, वहां वह निम्नलिखित तालिका में निर्दिष्ट दरों पर मकान किराया भत्ता के लिए पात्र होगा, अर्थात्: -

तालिका

क्रं. सं.	कार्य स्थल	आवास किराया भत्ता
(1)	(2)	(3)
1.	ग्रुप ए में प्रमुख "ए" श्रेणी के शहर और परियोजना क्षेत्र केंद्र	वेतन का 9.0%
2.	क्षेत्र I में अन्य स्थान और समूह बी में परियोजना क्षेत्र केंद्र तथा गोवा राज्य	वेतन का 8.0 %

3.	अन्य स्थान	वेतन का 7.0 %
----	------------	---------------

बशर्ते कि यदि कोई अधिकारी किराए की रसीद प्रस्तुत करता है, तो उसे देय आवास किराया भत्ता उसके द्वारा अपने वेतनमान, जिसमें वह पदस्थ है, के पहले चरण के 0.50% से अधिक प्रदत्त वास्तविक किराया या उपरोक्त तालिका के कॉलम (2) में उल्लिखित उपरोक्त दरों के अनुसार देय आवास किराया भत्ता के अधिकतम 150 प्रतिशत होगा।

नोट:- अधिकारियों के आवास किराया भत्ता के दावे उनके स्वामित्व आवास की लागत से जुड़े हैं जो अब आवास किराया भत्ता के 150 प्रतिशत तक सीमित रहेंगे।

8. उक्त विनियमों के विनियम 23 में, —

(क) उप-विनियम (1), (2), (3), (4), और (5) हेतु, निम्नलिखित उप-विनियमों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी नीचे दी गई तालिका के कॉलम (1) में उल्लिखित स्थान पर सेवारत है, तो उस स्थान के समक्ष कॉलम (2) में उल्लिखित दर पर एक नगर प्रतिपूरक भत्ता देय होगा: —

तालिका

क्रं सं	स्थान	दर
(1)	(2)	(3)
1.	क्षेत्र 1 और उससे ऊपर के स्थान और गोवा राज्य	रु. 1400/- प्रति माह
2.	पांच लाख और उससे अधिक की आबादी वाले स्थान तथा राज्य की राजधानियां और चंडीगढ़, पुडुचेरी और पोर्ट ब्लेयर।	रु. 1150/- प्रति माह

(2) नवंबर, 2017 को और उसके बाद से, विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में निर्दिष्ट किए अनुसार होंगी।

(3) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से यदि कोई अधिकारी परियोजना क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट क्षेत्र में सेवारत है जो ग्रुप ए या ग्रुप बी में आता है, तो वह क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार क्रमशः ग्रुप 'ए' या ग्रुप 'बी' के अनुसार रु. 600/- प्रति माह या रु. 525/- प्रति माह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र होगा।

(4) 1 नवंबर, 2020 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को शैक्षणिक वर्ष के मध्य में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या अधिक बच्चे पूर्व स्थान पर स्कूल या कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो वह सभी बच्चों के संबंध में बाद वाले स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षणिक वर्ष के अंत तक रु. 1650/- प्रति माह मध्य शैक्षणिक वर्ष स्थानांतरण भत्ते के लिए पात्र होगा, बशर्ते कि यदि सभी बच्चे पूर्व स्थान पर पढ़ना बंद कर देते हैं तो यह भत्ता बंद हो जाएगा।

(5) 1 नवंबर, 2020 को और उसके बाद से, यदि कोई अधिकारी बैंक से बाहर सेवा हेतु प्रतिनियुक्त है, तो वह उस पद, जिस पर वह प्रतिनियुक्त है, से जुड़ी परिलब्धियों को प्राप्त करने का विकल्प चुन सकता है, या वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.6000 प्रति माह के अध्यधीन प्रतिनियुक्ति भत्ता और ऐसे अन्य भत्ते प्राप्त कर सकता है, जो उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात होने पर प्राप्त करता,:

बशर्ते कि यदि उसे किसी ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाता है जो उसी स्थान पर स्थित है जहां उसकी प्रतिनियुक्ति से ठीक पहले उसकी तैनाती थी, तो उसे अपने वेतन का 4 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा जो अधिकतम रु. 3000/- प्रतिमाह होगा:

बशर्ते कि बैंक के प्रशिक्षण प्रतिष्ठान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त अधिकारी अपने वेतन के 4 प्रतिशत की दर से अधिकतम रु.3000 प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ते के लिए पात्र होगा।";

(बी) उप-विनियम (8) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(8) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से, यदि एक दिन के दौरान कार्य घंटों को न्यूनतम दो घंटे के अंतराल के साथ

विभाजित किया जाता है, तो अधिकारी रु. 300 प्रतिमाह की दर से विभाजित ड्यूटी भत्ते के लिए पात्र होगा।";

(सी) उप-विनियम (10) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(10) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से, अधिकारी नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट पर्वतीय और ईंधन भत्ते के लिए पात्र होगा, अर्थात्: —

सारणी

स्थान	दर
(1)	(2)
(i) 1000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाले स्थान लेकिन 1500 मीटर से कम और मकरा टाउन	वेतन का 2% अधिकतम रु.1125 प्रति माह के अध्यक्षीन
(ii) 1500 मीटर और उससे अधिक लेकिन 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 2.5% अधिकतम रु.1500 प्रति माह के अध्यक्षीन
(iii) 3000 मीटर और उससे अधिक की ऊंचाई वाला स्थान	वेतन का 5% अधिकतम रु.3000 प्रति माह के अध्यक्षीन

(डी) उप-विनियम (10) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(11) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से कोई भी अधिकारी रु. 600/- प्रतिमाह के शैक्षणिक भत्ते तथा उस पर महंगाई भत्ते के लिए पात्र होगा।"

(12) 1 नवंबर, 2017 को और उसके बाद से ऐसे अधिकारी रु. 700/- प्रतिमाह के निश्चित भत्ते के लिए पात्र होंगे, जो नगर प्रतिपूरक भत्ते के लिए पात्र क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में तैनात हैं। इस निश्चित भत्ते को महंगाई भत्ते, सेवानिवृत्ति लाभ, अर्थात् राष्ट्रीय पेंशन योजना, भविष्य निधि और ग्रेच्युटी सहित पेंशन के भुगतान के लिए परिकलित नहीं जाएगा।

(13) वित्तीय वर्ष 2020-21 से, सभी अधिकारियों को परिचालन लाभ या शुद्ध लाभ के आधार पर सामान्य वेतन के अतिरिक्त वार्षिक रूप से प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन देय होगा। नीचे उल्लिखित प्रदर्शन से जुड़ा प्रोत्साहन मैट्रिक्स बैंक के वार्षिक प्रदर्शन के आधार पर देय राशि (वेतन के दिनों की संख्या = मूल + महंगाई भत्ता) तय करेगा:

क्र. सं.	परिचालन लाभ में वर्ष दर वर्ष वृद्धि	वेतन (मूल + महंगाई भत्ता) भुगतान किए जाने वाले दिनों की संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	शून्य
2.	5% to 10%	5 दिन
3.	> 10% to 15%	10 दिन*
4.	> 15%	15 दिन*

*तीसरा और चौथा स्लैब तभी देय होगा जब बैंक का शुद्ध लाभ हो। यदि बैंक के परिचालन लाभ में 5 प्रतिशत या उससे अधिक की वृद्धि हुई है, लेकिन शुद्ध लाभ नहीं है, तो न्यूनतम 5 दिन का दूसरा स्लैब देय होगा।

9. उक्त विनियमों के विनियम 24 में, उप-विनियम (1) के लिए निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्-

"(1)" 1 नवंबर, 2017 को और उस दिन से, एक अधिकारी अपने और परिवार के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, जो अधिकारी के स्वयं के प्रमाण पत्र के आधार पर इस तरह के उपचित खर्च के लिए दावा की गई राशि के लिए

खातों के विवरण द्वारा समर्थित हो, जैसा कि नीचे तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

तालिका

क्र.	श्रेणी	प्रतिपूर्ति की अधिकतम सीमा
(1)	(2)	(3)
1.	कनिष्ठ प्रबंधन और मध्यम प्रबंधन श्रेणी	रु.10300/- प्रति वर्ष या उपगत की गई राशि जो भी कम हो
2.	वरिष्ठ प्रबंधन और शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	रु.12300/- प्रति वर्ष या उपगत की गई राशि जो भी कम हो

नोट :

- किसी अधिकारी को अप्रयुक्त चिकित्सा सहायता संचित करने की अनुमति दी जा सकती है ताकि यह किसी भी समय ऊपर प्रदान की गई अधिकतम राशि के तीन गुना से अधिक न हो; या
- वर्ष 2017 के लिए, चिकित्सा सहायता योजना के अंतर्गत चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति को दो महीनों, यानी नवंबर, 2017 और दिसंबर, 2017 के लिए आनुपातिक रूप से बढ़ाया जाएगा।

10. उक्त विनियमों के विनियम 25 में, उप-विनियम (2) के लिए, निम्नलिखित उप-विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

"(2) उप-विनियम (1) में कुछ भी शामिल होने के बावजूद, बैंक के लिए यह विकल्प खुला होगा कि वह अधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने पर 1 नवंबर, 2017 को और उस दिन से किसी अधिकारी को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराएगा, जो उस वेतनमान के पहले चरण में मूल वेतन जिसमें वह पदस्थ है, के 0.50 प्रतिशत की राशि के बराबर है या आवास के लिए मानक किराया, जो भी कम हो।

बशर्ते कि जहां अधिकारी को ऐसे आवास पर फर्नीचर प्रदान किया जाता है, वहां बैंक द्वारा उस वेतनमान, जिसमें वह पदस्थ है, के पहले चरण में मूल वेतन के 0.10 प्रतिशत के बराबर अतिरिक्त राशि वसूल की जाएगी :

बशर्ते यह भी कि जहां बैंक द्वारा ऐसी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाती है, वहां बिजली, पानी, गैस और वातावरण संरक्षण (कंजर्वेन्सी) का प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किया जाएगा।"

11. उक्त विनियम के विनियम 32 में, उप-विनियम (2) में, परंतुक (प्रोविज़ो) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

स्पष्टीकरण - इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि-

(क) वर्ष 2017 या किसी भी बाद के वर्षों में उपयोग न किया गया आकस्मिक अवकाश आगामी पांच वर्षों में समाप्त हो जाएगा;

(ख) 1 नवंबर, 2020 को और उस दिन से, अधिकारी द्वारा उपयोग न किया गया आकस्मिक अवकाश चिकित्सा आधार पर अनुमत होगा और लगातार चार दिनों से अनधिक ऐसे उपयोग न किए गए आकस्मिक अवकाश की अवधि के लिए किसी चिकित्सा प्रमाण-पत्र की आवश्यकता नहीं है।"

12. उक्त विनियमों के विनियम 33 में,—

(क) उप-विनियम (4) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:—

“(4) 1 जून, 2015 को और उस दिन से, विशेषाधिकार अवकाश अधिकतम दो सौ सत्तर दिनों तक संचित किया जा सकेगा, सिवाय इसके कि अवकाश के लिए आवेदन किया गया हो और उसे अस्वीकार कर दिया गया हो:

बशर्ते कि विशेषाधिकार अवकाश का नकदीकरण अधिकतम दो सौ चालीस दिनों तक सीमित होगा :

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि कैलेंडर वर्ष 2020 से, कोई अधिकारी अपनी पसंद के किसी भी त्यौहार के समय प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए पांच दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए भी पात्र होगा और कोई अधिकारी जो 1 जनवरी, 2020 को पचपन वर्ष या उससे अधिक की आयु पूरी कर चुका हो, वह एक बारगी उपाय के रूप में अपनी सेवानिवृत्ति तक प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के लिए सात दिनों की दर से विशेषाधिकार अवकाश के नकदीकरण के लिए पात्र होगा।”:

(ख) उप-विनियम (4) के पश्चात, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

“(5) विशेषाधिकार अवकाश लेने के इच्छुक अधिकारी को अवकाश किराया रियायत के प्रयोजन को छोड़कर सामान्यतः ऐसे अवकाश लेने के अपने इरादे की कम से कम दस दिन पहले सूचना देनी होगी।

(6) बीमारी के कारण लिया गया विशेषाधिकार अवकाश, जब अधिकारी के बीमारी अवकाश खाते में कोई जमा नहीं है, विशेषाधिकार अवकाश लेने के अवसर के रूप में नहीं गिना जाएगा।”

13. उक्त विनियम के विनियम 34 में उप-विनियम (4) के पश्चात निम्नलिखित उप-विनियम शामिल किया जाएगा, अर्थात्:-

“(5) महिला अधिकारी अपने आठ वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की बीमारी के लिए चिकित्सा प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के अधीन बीमारी अवकाश ले सकती हैं।”

14. उक्त विनियम के विनियम 35 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“35 अतिरिक्त बीमारी अवकाश:- (1) 1 जनवरी, 1989 को और उस दिन से, जहां किसी अधिकारी ने चौबीस वर्ष की सेवा पूर्ण की है, वह चौबीस वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से अतिरिक्त बीमारी अवकाश के लिए पात्र होगा, जो अधिकतम तीन माह के अतिरिक्त बीमारी अवकाश के अधीन होगा।

(2) 1 नवम्बर, 2017 को और उस दिन से, जहां किसी अधिकारी ने तीस वर्ष की सेवा की है, वह तीस वर्ष से अधिक की सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए एक माह की दर से अतिरिक्त बीमारी अवकाश के लिए पात्र होगा, जो अधिकतम तीन माह की अतिरिक्त बीमारी अवकाश के अधीन होगा:

बशर्ते कि अधिकारी की संपूर्ण सेवा में बीमारी अवकाश की कुल संख्या सात सौ बीस दिन से अधिक नहीं होगी:

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि 29 जून, 1999 को या उसके बाद लिए गए अतिरिक्त बीमारी अवकाश के मामले में, विनियम 34 के उप-विनियम (2) के अनुसार अतिरिक्त अवकाश के संराशीकरण की अनुमति दी जा सकेगी।”

15. उक्त विनियम के विनियम 36 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“ 36. मातृत्व अवकाश:— (1) मातृत्व अवकाश के मामले में,—

(क) कोई महिला कर्मचारी किसी एक अवसर पर अधिकतम छह महीने की अवधि के लिए तथा अपनी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम बारह महीने के लिए मूल वेतन पर मातृत्व अवकाश के लिए पात्र होगी:

बशर्ते कि जुड़वा बच्चों के जन्म के मामले में, मातृत्व अवकाश की अवधि आठ महीने होगी :

इसके अलावा यह भी प्रावधान है कि मातृत्व अवकाश आकस्मिक अवकाश को छोड़कर किसी भी अन्य प्रकार के अवकाश के साथ जोड़कर लिया जा सकता है;

(ख) गर्भपात, गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति या गर्भपात (गर्भस्राव) के मामले में, कोई महिला कर्मचारी सक्षम चिकित्सक अर्थात् अर्हताप्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ के चिकित्सा प्रमाणपत्र या सलाह के आधार पर छह सप्ताह तक का मातृत्व

अवकाश ले सकती है। गर्भपात या गर्भावस्था की चिकित्सीय समाप्ति या गर्भपात (गर्भस्राव) से जुड़ी चिकित्सीय जटिलताओं वाले विशेष या असाधारण मामलों में, सक्षम चिकित्सक (अर्हताप्राप्त स्त्री रोग विशेषज्ञ) की सलाह पर छह सप्ताह से अधिक मातृत्व अवकाश लिया जा सकता है, लेकिन सेवा की पूरी अवधि के दौरान बारह महीने की समग्र सीमा के भीतर किसी एक अवसर पर केवल छह महीने तक का ही अवकाश लिया जा सकता है;

(ग) बारह महीने की समग्र अवधि के भीतर, हिस्टेरेक्टॉमी के मामले में अधिकतम साठ दिनों तक की छुट्टी भी ली जा सकती है।

नोट: उन कर्मचारियों के मामले में जिन्होंने बारह महीने का पूर्ण मातृत्व अवकाश लेकर उसे समाप्त कर दिया है, चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के अधीन, अतिरिक्त पंद्रह दिनों की छुट्टी स्वीकृत की जाएगी;

(घ) एक निःसंतान महिला अधिकारी एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए सेवा के दौरान एक बार छुट्टी ले सकती है, जो निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अधीन अधिकतम नौ महीने की अवधि के लिए है :-

- (i) केवल एक बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी दी जाएगी;
- (ii) एक बच्चे को उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से गोद लेना होगा और अधिकारी ऐसी छुट्टी की मंजूरी के लिए बैंक को दत्तक विलेख प्रस्तुत करेगी;
- (iii) स्थायी अंशकालिक कर्मचारी भी बच्चे को गोद लेने के लिए छुट्टी के पात्र हैं;
- (iv) बायोलॉजिकल माँ को भी उन मामलों में छुट्टी उपलब्ध होगी जहां बच्चे का जन्म सरोगेसी के माध्यम से हुआ हो; तथा
- (v) सेवा की सम्पूर्ण अवधि के दौरान छुट्टी, बारह महीने की समग्र पात्रता के भीतर प्राप्त की जाएगी।

(ङ) बारह महीने की कुल अवधि के भीतर, निम्नलिखित स्त्री रोग संबंधी बीमारियों या उपचारों के कारण अस्पताल में भर्ती होने की स्थिति में अधिकतम तीस दिनों तक छुट्टी का लाभ उठाया जा सकता है, अर्थात्: -

- (i) एयूबी (असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव);
- (ii) डिम्बग्रंथि ट्यूमर;
- (iii) ट्यूबेक्टोमी या ट्यूबेक्टोमी रिवर्सल;
- (iv) प्रसवोत्तर अवसाद (पीपीडी);
- (v) प्रसवोत्तर रक्तस्राव (पीपीएच);
- (vi) तीव्र श्रोणि सूजन रोग (तीव्र पीआईडी);
- (vii) डिसफंक्शन गर्भाशय रक्तस्राव; डिसफंक्शन (डीयूबी)।

(2) 1 जून 2015 से, पुरुष अधिकारी कर्मचारी जिनके अधिकतम दो जीवित संतानें हैं, वे अपनी पत्नी की प्रसूति के दौरान पंद्रह दिनों के पितृत्व अवकाश के लिए पात्र होंगे, जिसे आकस्मिक छुट्टी के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार की छुट्टी के साथ जोड़ा जा सकता है:

बशर्ते कि छुट्टी बच्चे के जन्म की तारीख से पंद्रह दिन पूर्व या आगामी छह माह तक आवेदित की जाएगी।"

बशर्ते यह भी कि दो जीवित बच्चों वाले पुरुष कर्मचारी को एक वर्ष से कम उम्र के बच्चे को कानूनी रूप से गोद लेने के लिए उपर्युक्त पितृत्व अवकाश की अनुमति दी जाएगी।

16. उक्त विनियमों के विनियम 37 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“37. असाधारण अवकाश:- (1) कोई अधिकारी संपूर्ण सेवा अवधि के दौरान अधिकतम चौबीस माह के लिए बिना वेतन पर असाधारण अवकाश के लिए पात्र होगा।

(2) कोई अधिकारी किसी एक अवसर पर तीन माह से अधिक अवधि के लिए असाधारण अवकाश ले सकता है तथा गहन चिकित्सीय परिस्थितियों में वह किसी एक अवसर पर चार माह तक का असाधारण अवकाश ले सकता है।

नोट: चिकित्सा आधार पर असाधारण अवकाश लेने के कारण कर्मचारी को वरिष्ठता की कोई हानि नहीं होगी।”

17. उक्त विनियमों के विनियम 37ए के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

“37ए. - विशेष आकस्मिक अवकाश और विशेष अवकाश :- (1) 1 नवंबर, 2020 से, कोई अधिकारी कर्मचारी ऐसे अवसरों पर विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा, जब वह शाखा जहां अधिकारी कार्यरत है या वह स्थान जहां वह रह रहा है, कर्फ्यू, दंगे, निषेधाज्ञा, प्राकृतिक आपदा, बाढ़ आदि से प्रभावित हो।

(2) 1 नवंबर, 2020 से, कोई शारीरिक या अस्थि विकलांग अधिकारी चार दिन के विशेष आकस्मिक अवकाश के लिए पात्र होगा।

(3) किसी अधिकारी को विशेष आकस्मिक अवकाश और कोई विशेष अवकाश भी प्रदान किया जा सकता है, जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।

18. उक्त विनियम के विनियम 41 में, उप-विनियम (4) में, खंड (ए) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

“(क) विराम भत्ता:— 1 नवंबर, 2020 को और उस दिन से, तालिका के कॉलम (1) में दिए गए ग्रेड या वेतनमान में कोई अधिकारी कॉलम (2) में दी गई संगत दरों पर 'प्रतिदिन' विराम भत्ते का पात्र होगा, अर्थात् :-

क्र.सं.	अधिकारी की श्रेणी/ वेतनमान	महानगरीय रू.	मेजर ए शहर रू.	एरिया I रू.	अन्य स्थान रू.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	वेतनमान VI और उससे ऊपर के अधिकारी	2700	1950	1650	1425
2.	वेतनमान IV और V के अधिकारी	2250	1950	1650	1425
3.	वेतनमान I, II और III के अधिकारी	1950	1650	1425	1200

बशर्ते कि जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि आठ घंटे से कम किन्तु चार घंटे से अधिक हो, वहां उपर्युक्त दरों से आधी दर पर विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण:- विराम भत्ते की गणना करने के प्रयोजन के लिए "प्रतिदिन" से तात्पर्य चौबीस घंटे की प्रत्येक अवधि या उसका कोई पश्चातवर्ती भाग होगा, जिसकी गणना हवाई यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय से और अन्य मामलों में प्रस्थान के निर्धारित समय से लेकर आगमन के वास्तविक समय तक की जाएगी और जहां अनुपस्थिति की कुल अवधि चौबीस घंटे से कम है, वहां "प्रतिदिन" से तात्पर्य आठ घंटे से कम नहीं की अवधि होगी।”

19. उक्त विनियमों के विनियमन 42 में उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(3) 1 नवंबर, 2020 से स्थानांतरित होने वाले अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन, सामान का बीमा आदि से जुड़े खर्चों के लिए एकमुश्त राशि के पात्र होंगे, जैसा कि नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट है, अर्थात्:-

“तालिका

क्र.सं.	ग्रेड या स्केल	राशि
(1)	(2)	(3)
1.	शीर्ष कार्यपालक और वरिष्ठ प्रबंधन (स्केल IV और उससे ऊपर के अधिकारी)	रु.30,000/-
2.	मध्य प्रबंधन और कनिष्ठ प्रबंधन (स्केल III तक के अधिकारी)	रु.25,000/-.

20. उक्त विनियमनों के विनियमन 45 में, उप-विनियम (4) के नोट से पहले, निम्नलिखित प्रावधान शामिल किए जाएंगे, अर्थात्: -

“बशर्ते कि परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना (नई पेंशन योजना) के अंतर्गत आने वाले अधिकारियों के संबंध में, बैंक 11 नवंबर, 2020 से वेतन और महंगाई भत्ते का चौदह प्रतिशत अंशदान करेगा:

बशर्ते कि नई पेंशन योजना के सेवा प्रदाता या निधि प्रबंधक के सेवा प्रभार का वहन वित्तीय वर्ष 2020-21 से बैंक द्वारा किया जाएगा।”

21. उक्त विनियमों की अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्:—

“अनुसूची

(विनियमन 23 का उप-विनियमन (2) देखें)

1 नवंबर, 2017 से कोई भी अधिकारी विशेष क्षेत्र भत्ते के लिए तब तक पात्र होगा जब तक कि उसे नीचे दी गई तालिका में निर्दिष्ट अनुसार पूर्णतः या आंशिक रूप से वापस नहीं ले लिया जाता या संशोधित नहीं कर लिया जाता, अर्थात्:—

तालिका

विशेष क्षेत्र भत्ता

क्र.सं.	क्षेत्र	भत्ता (रु.)	
		रु.36,001/- से कम वेतन	रु.36,001/-से अधिक वेतन
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	मिजोरम		
	चिम्पुइपुई जिला और लुंगलेई जिले के लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर से आगे के क्षेत्र;	4000	5200
	(ख) लुंगलेई शहर से 25 किलोमीटर दूर के क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण लुंगलेई जिला;	3200	4200
	(ग) संपूर्ण आइजोल जिला	2400	3000
2.	नागालैंड	3200	4200
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		
	(क) उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान, निकोबार और नाकोर्डम द्वीप	4000	5200

	(ख) दक्षिण अंडमान (पोर्ट ब्लेयर सहित)	3200	4200
4.	सिक्किम	4000	5200
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	4000	5200
6.	असम	640	800
7.	मेघालय	640	800
8.	त्रिपुरा (क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र (ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण त्रिपुरा।	3200 2400	4200 3000
9.	मणिपुर	2400	3000
10.	अरुणाचल प्रदेश (क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र (ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर सम्पूर्ण अरुणाचल प्रदेश।	4000 3200	5200 4200
11.	जम्मू और कश्मीर (1) कठुआ जिला: नियाबतबानी, लोही, मल्हार और मछोड़ी	4000	5200
	(2) उधमपुर जिला: (i) डुडु बसंतगढ़, लैंडर भमागइलका, भाग 2(बी) में शामिल क्षेत्रों को छोड़कर। (ii) तहसील मोहरे में कंबन की ओर से गोयल तक का क्षेत्र और केसी की ओर से अरनास तक का क्षेत्र।	4000 3200	5200 4200
	(3) डोडा जिला: किश्तवाड़ तहसील में पैडर और नियाबत नौगाम के इलाक़ास	4000	5200
	(4) लेह जिला : जिले के सभी स्थान	4000	5200
	(5) बारामूला जिला: (i) संपूर्ण गुरेज़-निराबत, तंगदार उप-विभाजन और केरनइलाक़ा (ii) मोटचिल	4000 3200	5200 4200
	(6) पुंछ और राजौरी जिले: पुंछ और राजौरी जिले के क्षेत्र, पुंछ और राजौरी कस्बों और सुंदरबनी तथा दोनों जिलों के अन्य शहरी क्षेत्रों को छोड़कर।	2400	3000
	(7) ऐसे क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (6) में सम्मिलित नहीं हैं, किन्तु जो वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 किलोमीटर की दूरी के भीतर हैं या ऐसे स्थान हैं जिन्हें राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अपने कर्मचारियों के लिए सीमा भत्ते के लिए अर्हक घोषित किया जा सकता है।	2400	3000
12.	हिमाचल प्रदेश (1) चम्बा जिला (i) पांगी तहसील, भरमौर तहसील, पंचायतें: बड़गांव, बजोल, देवलकुगती, नयागाम और तुंदाह, गांव: ग्राम पंचायत जगत के घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा के कनारसी	4000	5200

(ii) भरमौर तहसील, ऊपर (ए) में शामिल पंचायतों और गांवों को छोड़कर।	3200	4200
(iii) भटियात तहसील में झंडरू पंचायत, चुराह तहसील, डलहौजी शहर (बनीखेत सहित)।	2400	3000
(2) किन्नौर जिला:		
(i) असरंग, छितकुल और हांगोकुनो/चारंग पंचायतें, 15/20 छोटाखंबा, नाथपा और रूपी, पूह उप-मंडल की ग्राम पंचायतों को शामिल करने वाला क्षेत्र, ऊपर निर्दिष्ट पंचायत क्षेत्रों को छोड़कर।	4000	5200
(ii) उपरोक्त (ए) में शामिल क्षेत्रों के अलावा संपूर्ण जिला।	3200	4200
(3) कुल्लू जिला:		
(i) निरमंड तहसील का 15/20 क्षेत्र, जिसमें खरगा, कुशवार और सरगा ग्राम पंचायतें शामिल हैं	4000	5200
(ii) [बाहरी सराज (निरमंड तहसील में जकात-खाना और बरो के गांवों को छोड़कर) और संपूर्ण जिला बाहरी सराज क्षेत्र और पंद्राबीस के परगना को छोड़कर, लेकिन तहसील निरमंड के जगत-खाना और बरो गांव सहित]	2400	3000
(4) लाहौल और स्पीति जिला:		
लाहौल और स्पीति का संपूर्ण क्षेत्र	4000	5200
(5) शिमला जिला :		
(i) रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र जिसमें कूट, लबाना-सदाना, सरपारा और चाडी-ब्रांडा की पंचायतें शामिल हैं।	4000	5200
(ii) डोरा-कावर तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, काशापथ तहसील और परगना सराहन के मुनीश, धोरीचैबीस।	3200	4200
(iii) चौपाल तहसील और परगना सराहन के घोरी, पंजगांव, पाटसनौ, नौबीस और तीन कोटी, तकलेश क्षेत्र की देवठी ग्राम पंचायत, परगना बाराबीस, रामपुर तहसील के परगना रामपुर का कस्बा रामपुर और घोरी नोग, शिमला शहर और इसके उपनगर (डल्ली, जटोग, कसुम्पटी, मशोबरा, तारादेवी और टूट्ट)।	2400	3000
(6) कांगड़ा जिला:		
(i) बारा भंगाल और छोटा भंगाल के क्षेत्र	3200	4200
(ii) कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित लेकिन धर्मशाला शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय-महिला आईटीआई, दारी, मैकेनिकल वर्कशॉप, रामनगर, बाल कल्याण और नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यालय, सकोह, निचले सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दूध आपूर्ति योजना, डुगियार, एचआरटीसी वर्कशॉप, सधेर, क्षेत्रीय मलेरिया कार्यालय, दारी, वन निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी, दारी, आईपीएच उप-मंडल, दान, बंदोबस्त कार्यालय, शामनगर, हिनवा परियोजना, शामनगर। कांगड़ा जिले का पालमपुर शहर जिसमें पालमपुर में एचपीकेवीवी परिसर और नगरपालिका सीमा के बाहर स्थित लेकिन पालमपुर शहर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय शामिल हैं-एच.पी. कृषि विश्वविद्यालय परिसर, पशु विकास कार्यालय/जर्सी फार्म, बनूरी, रेशम उत्पादन कार्यालय/इंडो-जर्मन कृषि कार्यशाला/एचपीपीडीब्ल्यूडी डिवीजन, बुंडला, विद्युत उप-डिवीजन, लोहना, डीपीओ निगम, बुंडला, विद्युत एचईएसईई डिवीजन, घुग्गर।	2400	3000

	(7)मंडी जिला: जोगिंदरनगर तहसील की छुहार घाटी, थुनाग तहसील की पंचायतें- बागरा, छतरी, छोटधार, गरागुशैन, गट्ट, गरयास, जंजैहली, जरयार, जोहार, कल्हणी, कलवन, खोलानाल, लोथ, सिलीबागी, सोमाचन, थाचधार, ताची, थाना, की पंचायतें धर्मपुर ब्लॉक- बिंगा, कमलाह, सकलाना, तनयार और ताराखोला, करसोग की पंचायतें तहसील - बालीधार, बागरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुडी, मंज, पेखी, सैंज, सराहन और तेबन, सुंदरनगर तहसील की पंचायतें - बोही, बटवाड़ा, धन्यारा, पौड़ा-कोठी, सेरी और शोजा।	2400	3000
	(1) सिरमौर जिला: बानी, बाखली (पच्छाद तहसील), भरोगभनेरी (पांवटा तहसील), बिड़ला (नाहन तहसील), डिब्बर (पच्छाद तहसील) और थानाकसोगा (नाहन तहसील) और थांसगिरि क्षेत्र की पंचायतें	2400	3000
	(9) सोलन जिला: मंगल पंचायत.	2400	3000
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपर्युक्त (1) से (9) में सम्मिलित नहीं हैं।	640	800
13.	उत्तर प्रदेश: चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तर काशी जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4000	5200
14.	उत्तराखंड: चमोली, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग और चंपावत जिलों के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र	4000	5200
15.	पश्चिम बंगाल दक्षिण 24 परगना जिला सुंदरबन क्षेत्र (डैम्पियर हॉज की रेखा के दक्षिण में), अर्थात्, भानातुश खली (रामपुरा), कुमिरमारी (बगना), झिंगखाली, सजनाखाली, गोसाबा, अमलामाथी (बिद्या), कैनिंग, कुलतली, पियाली, नलगराहा, रैदिघी, भांची, पाथरप्रतिमा, भागवतपुर, सप्तमुखी, नामखाना, सिकरपुर, काकद्वीप, सागर, मौसिनी, कालीनगर, हरोआ, हिंगलगंज, बसंती, कुएमारी, कुलटोला, घुशियोघाटा (कुल्टी)	1000	1000

के. राजेश कुमार, महाप्रबंधक

[विज्ञापन-III/4/असा./737/2024-25]

नोट : बैंक ऑफ महाराष्ट्र (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979 को भारत के राजपत्र, भाग III, खंड 4 में प्रकाशित किया गया था। इन विनियमों को बाद में निम्नलिखित अधिसूचनाओं के माध्यम से संशोधित किया गया: -

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना संख्या	सरकारी राजपत्र में प्रकाशित का दिनांक
1.	-----	07.12.1987	26.12.1987
2.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/14046/96	05.05.1997	17.05.1997

3.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/3169/2001	19.05.2001	16.06.2001
4.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/853/2003	11.02.2003	15.03.2003
5.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/2053/2006	21.03.2006	07.04.2006
6.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/5207/2006	30.05.2008	05.06.2008
7.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/1324/2017-18	01.03.2008	14.03.2018
8.	एएक्स-1/एसटी/ओएसआर/1325/2021-22	07.12.2021	14.12.2021

विवरणात्मक ज्ञापन

ये विनियम, जिन्हें पूर्वव्यापी प्रभाव दिया गया है, इस संबंध में संबंधित बैंकों द्वारा दिए गए विशिष्ट अधिदेश के आधार पर संयुक्त नोटों की सहमत शर्तों और नियमों के अनुसार सदस्य बैंकों की ओर से भारतीय बैंक संघ और बैंकों के शीर्ष स्तरीय अधिकारी एशोसिएशनों के बीच हस्ताक्षरित हैं। अतः ऐसे पूर्वव्यापी प्रभाव से किसी भी व्यक्ति के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

BANK OF MAHARASHTRA

NOTIFICATION

Pune, the 4th December, 2024

F. No.: AX1/ST/OSR/119/2024-25.—In exercise of the powers conferred by section 19, read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of the Bank of Maharashtra, after consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government, except as respects things done or omitted to be done in pursuance of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Financial Services, letter No. 4/2/2/2015-IR, dated the 18th December, 2020, on and from the 1st November, 2017 till the date of publication of this notification in the Official Gazette, hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979, namely:—

- (1) These regulations may be called the Bank of Maharashtra (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2024.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- In the Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979 (hereinafter referred to as the said regulations), in regulation 3,- (i) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely:-

“(f) “family” for the purposes of medical facilities and for the purpose of leave fare concession means, the spouse of the officer, wholly dependent unmarried children (including step children and legally adopted children) wholly dependent physically and mentally challenged brother or sister with forty per cent. or more disability, widowed daughters and dependent divorced or separated daughters, sisters including unmarried or divorced or abandoned or separated from husband or widowed sisters and parents wholly dependent on the officer.

Explanation; —

- The expression “wholly dependent family member” shall mean such member of the family having an income not exceeding **₹12,000/- per month**. If the income of one of the parents exceeds **₹12,000/- per month** or the aggregate income of both the parents exceeds **₹12,000/- per month**, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the officer.
- A married female officer may include her natural parents or parents-in-law under the definition of family, but not both, provided that the parents or parents-in-law are wholly dependent on her.

Note 1: For the purpose of medical expenses reimbursement scheme, for all officers, i.e., male or female, any two of the dependent parents or parents-in-law shall be covered. The officer will have the choice to substitute either of the dependents or both.

Note 2: Physically challenged children of an officer to be defined as dependents irrespective of age or marital status, subject to income criteria.”;

(ii) for clause (i), the following clause shall be substituted, namely : —

“(i) “Managing Director” means the Managing Director and the Chief Executive Officer of the Bank;”.

3. In regulation 4 of the said regulations,-

(i) in sub-regulation (6), the *Explanation* shall be omitted;

(ii) for sub-regulations (7) and (8), the following sub-regulations shall be substituted namely : —

“(7) With effect from the 1st November, 2017, the scales of pay specified against each grade shall be as under : —

(a) Top Executive Grade

Scale VII = ₹116120 – 3220/4 – 129000

Scale VI = ₹ 104240 – 2970/4 – 116120

(b) Senior Management Grade

Scale V = ₹ 89890 – 2500/2 – 94890 – 2730/2 - 100350

Scale IV = ₹ 76010 – 2220/4 – 84890 – 2500/2 – 89890

(c) Middle Management Grade

Scale III = ₹ 63840-1990/5– 73790 - 2220/2 - 78230

Scale II = ₹ 48170–1740/1 - 49910 -1990/10 - 69810

(d) Junior Management Grade

Scale I = ₹ 36000-1490/7- 46430-1740/2-49910-1990/7-63840.

Explanation.- Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on the 31st October, 2017 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November, 2017 on stage-to-stage basis, i.e., on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(8) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3), (4), (5), (6) and (7) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

(9) (a) With effect from the 1st day of November, 2012, officers shall be paid special allowances as under: —

Scale I – III - 7.75 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 10% of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII - 11 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon.

(b) With effect from the 1st day of November, 2017, officers shall be paid special allowances as under: —

Scale I – III - 16.40 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale IV – V - 19 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon

Scale VI – VII - 20 % of Basic Pay plus applicable Dearness Allowance thereon:

Note: The special allowance referred to in clauses (a) and (b) of sub-regulation (9) with applicable dearness allowance thereon shall not be reckoned for superannuation benefits, such as pension including New Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.”.

4. In regulation 5 of the said regulations, -

(i) for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely: -

“(1) Subject to the provisions of sub-regulations (7) of regulation 4, on and from the 1st November, 2017, the increments shall be granted subject to the following, namely:—

(a) the increments specified in the scales of pay set out in sub-regulations (7) of regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due;

- (b) one year after reaching maximum in their respective scales, officers in Scale I and Scale II, shall be granted further increments including stagnation increments in the next higher Scale only as specified in clause (c) below subject to their crossing the efficiency bar;
- (c) officers in Junior Management grade Scale I who have moved to scale of pay for Middle Management grade Scale II in terms of clause (b) after reaching maximum of the higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments for every two completed years of service of which the first two shall be Rs.1990/- each and the next three of Rs.2220/- each:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1st November 2017, whichever is later;

- (d) officers in middle management grade Scale II who have moved to scale of pay for middle management grade Scale III in terms of clause (b), after reaching maximum of higher Scale, shall be eligible for five stagnation increments of Rs.2220/- each for every two completed years of service:

Provided that the officer shall be eligible for the fifth stagnation increment two years after release of fourth stagnation increment or on the 1st November 2017, whichever is later;

- (e) officer in substantive middle management grade Scale III i.e., those who are recruited in or promoted to middle management grade Scale III shall be eligible for six stagnation increments out of which first four stagnation increments of Rs.2220/- each will be granted for every two years of completed service after reaching the maximum and the next two stagnation increments of Rs.2500/- each shall be granted for every two years of completed service after receiving the fourth stagnation increment:

Provided that the sixth stagnation increment shall be released two years after release of fifth stagnation increment or on the 1st November 2017, whichever is later;

- (f) officers in senior manager grade Scale IV shall be eligible for two stagnation increments after reaching the maximum of scale, for every two completed years of service, of which first stagnation increment shall be of Rs.2500/- and the second stagnation increment shall be of Rs.2730/-:

Provided that the officer shall be eligible for the second stagnation increment two years after release of first stagnation increment or on the 1st November 2017, whichever is later;

- (g) the stagnation increments received by the officer from Scale I to Scale IV during their service in bank as on the 1st November, 2017 as per periodicity hereinbefore would be readjusted from three years periodicity to two years periodicity from the date of reaching their maximum and officer shall be notionally eligible for stagnation increments with effect from the 1st November, 2017 as per the revised periodicity which will qualify for superannuation benefits:

Provided that monetary benefit on account of such revised and readjusted periodicity of stagnation increments shall be payable from the 1st November, 2020 or the actual date of entitlement, whichever is later:

- (h) officer in senior management grade Scale V shall be eligible for one stagnation increment of Rs.2970/- two years after reaching the maximum scale of pay or on the 1st November 2020, whichever is later:

Provided that such increments shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Explanation.- Grant of such increments in the next higher scale under this sub-regulation shall not amount to promotion and the privileges, perquisites, duties and responsibilities of the officers shall continue as of their substantive posts.”;

- (ii) in sub-regulation (2), in the *Explanation*, after clause (g) and before the Note, the following clause shall be inserted, namely:—

“ (h) On and from the 1st day of November, 2017, other things being equal, the quantum of professional qualification pay shall stand revised as specified in the Table below:-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers Part I	(i) Rs.1020 per month one year after reaching maximum of the Scale.
--	---

Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	<p>(i) Rs. 1020 per month one year after reaching maximum of the Scale.</p> <p>(ii) Rs.2550 per month two years after reaching maximum of the Scale:</p>
--	--

Provided that an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of the scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of professional qualification pay and the release of subsequent installments of professional qualification pay shall be with reference to the date of release of first installment of such professional qualification pay.”;

(iii) in sub-regulation (3), -

(a) in clause (f), after the Table, Notes (i) to (vi) shall be omitted:

(b) after clause (f), the following clause shall be inserted, namely :—

“(g) on and from the 1st November, 2017, other things being equal, Fixed Personal Pay together with House Rent Allowance shall be at the following rates and shall remain frozen for the entire period of service:—

TABLE

Sl. No.	Increment component (Rs.)	Dearness Allowance as on the 1 st November, 2017 on the increment components (Rs.)	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided (Rs.)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	1990	53	2043
2.	2220	59	2279
3.	2500	66	2566
4.	2730	73	2803
5.	2970	79	3049
6.	3220	86	3306

Note:

- (i) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay as indicated under column (3) of the Tables in clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) of this sub-regulation shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be the aggregate amount specified under columns (1) and (2) of the aforesaid Table and House Rent Allowance drawn by the concerned officer when the last increment of the relevant scale of pay as specified in sub-regulations (2),(3), (4), (5) (6) and (7) of regulation 4 is earned.
- (iii) Only officers who are in the service of the Bank on or before the 1st November, 1993, will be eligible for Fixed Personal Pay one year after reaching the maximum scale pay, they are placed.
- (iv) On and from the 1st November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay:

Provided that where any installment of professional qualification pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after the 1st November 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of professional qualification pay, if any, shall be released on the 1st November, 2000.

- (v) The increment component of Fixed Personal Allowance or Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (vi) An officer who has earned the advance increment as in clause (a) above shall draw the quantum of 'Fixed' Personal Allowance or Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c), (d), (e), (f) and (g) above, one year after reaching the maximum of the scale.
5. In regulation 20 of the said regulations, in sub-regulation (1), in clause (c), the words "Chairman and" shall be omitted.
6. In regulation 21 of the said regulations, –
- (a) in sub-regulation (6), in the *Explanation* in clause (b), for the brackets, letters and words "(f) and (g)", the brackets, letters and words, "(f), (g) and (h)" shall be substituted.
- (b) after sub-regulation (6), the following sub-regulation shall be inserted, namely :—
- “(7) On and from the 1st day of November, 2017, dearness allowance shall be payable for every rise or fall of four points over 6352 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960=100 at 0.07% of Pay.”.
7. In regulation 22 of the said regulation, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-
- “(1) On and from the 1st November, 2017,—
- (a) where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, shall be recovered from him;
- (b) where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank, he shall be eligible for House Rent Allowance at the rates specified in the following Table, namely: —

TABLE

Sl. No.	Place of work	House Rent Allowance
(1)	(2)	(3)
1.	Major "A" Class Cities and Project Area Centres in Group A	9.0% of Pay
2.	Other places in Area I and Project Area Centres in Group B and State of Goa	8.0% of Pay
3.	Other places	7.0% of Pay:

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for the residential accommodation in excess over 0.50 per cent. of pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed with a maximum of 150 per cent. of the House Rent Allowance payable as per aforesaid rates mentioned in column (2) of the above Table.

Note : The claims of officers for House Rent Allowance linked to the cost of their ownership accommodation shall be also be restricted to 150 per cent. of House Rent Allowance as hitherto.”.

8. In regulation 23 of the said regulations,—
- (A) for sub-regulations (1), (2), (3), (4) and (5), the following sub-regulations shall respectively be substituted, namely:—
- “(1) On and from the 1st November, 2017, if an officer is serving in a place mentioned in column (1) of the Table below, a city compensatory allowance at the rate mentioned in column (2) thereof against that place shall be payable.

TABLE

Sl. No.	Places	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Places in Area 1 and above and in the State of Goa	Rs. 1400/- per month
2.	Places with population of five lakhs and over and state capitals and Chandigarh, Puducherry and Port Blair	Rs. 1150/- per month

- (2) On and from the 1st November, 2017, the rates of special areas allowances shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from the 1st November, 2017, if an officer is serving in an area specified as Project Area falling in Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.600/- per month or Rs.525/- per month according to the classification of area as Group 'A' or Group 'B' respectively.
- (4) On and from the 1st November, 2020, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid-academic year transfer allowance of Rs 1650/- per month from the date he reports to the latter place upto the end of the academic year in respect of all the children, provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.
- (5) On and from the 1st November, 2020, if an officer is deputed to serve outside the Bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed, or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75 per cent. of pay subject to a maximum of Rs.6000/- per month and such other allowances he would have drawn had he been posted in the Bank's service at that place:

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs. 3000/- per month:

Provided further that an officer on deputation to the training establishment of the Bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at the rate of 4 per cent. of his pay subject to a maximum of Rs.3000 per month.”;

- (B) for sub-regulation (8), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(8) On and from the 1st November, 2017, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.300 per month.”;

- (C) for sub-regulation (10), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(10) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for the hill and fuel allowance as specified in the Table below, namely: —

TABLE

Sl. No.	Place	Rate
(1)	(2)	(3)
1.	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.1125/- per month
2.	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.1500/- per month
3.	Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.3000/- per month”;

- (D) after sub-regulation (10), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(11) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for learning allowance of Rs 600/- per month along with Dearness Allowance thereon.”.

(12) On and from the 1st November 2017 an officer shall be eligible for a fixed allowance of Rs.700/- per month who are posted in areas other than the areas that are eligible for City Compensatory Allowance. This fixed allowance shall not be reckoned for payment of Dearness Allowance, superannuation benefits, viz, pension including National Pension Scheme, Provident Fund and Gratuity.

(13) From the financial year 2020-21, Performance Linked Incentive shall be payable to all officers annually based on Operating Profit or Net Profit over and above the normal salary payable. The Performance Linked Incentive matrix mentioned below shall decide the amount payable (in number of days of pay = Basic + Dearness Allowance) depending on the annual performance of the Bank:

Sl. No.	Year on Year growth in operating profit	Number of days for which salary (Basic + Dearness Allowance) shall be paid
(1)	(2)	(3)
1.	< 5%	Nil
2.	5% to 10%	5 days
3.	> 10% to 15%	10 days*
4.	> 15%	15 days*

*3rd and 4th slabs are payable only if the Bank has Net Profit. If a Bank has growth in operating profit of 5 per cent. and more, but there is no Net Profit, then minimum 2nd slab of 5 days shall be payable.”.

9. In regulation 24 of the said regulations, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(1) On and from the 1st November, 2017, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer’s own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in the Table below, namely:—

TABLE

Sl. No.	Grade	Maximum limit of reimbursement
(1)	(2)	(3)
1.	Junior Management and Middle Management Grade	Rs.10300/- per annum or the amount incurred whichever is less
2.	Senior Management and Top Executive Grade	Rs.12300/- per annum or the amount incurred whichever is less

Note : (i) an officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above; or

(ii) for the year 2017, the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for two months, that is, November, 2017 and December, 2017.”.

10. In regulation 25 of the said regulations, for sub-regulation (2), the following sub-regulation shall be substituted, namely:—

“(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), it shall be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from the 1st November, 2017, a sum equal to 0.50 per cent. of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less:

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.10 per cent. of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed shall be recovered by the Bank from him:

Provided further that where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.”.

11. In regulation 32 of the said regulations, in sub-regulation (2), after the proviso, the following *Explanation* shall be inserted, namely:—

“**Explanation.-** for the purposes of this regulation, it is clarified that-

- casual leave not availed in the year 2017 or any subsequent years shall lapse in the following five year;
- on and from the 1st November, 2020, the unavailed casual leave by the officer shall be permitted on medical grounds and no medical certificate is required for the period of such unavailed casual leave at a stretch not exceeding four days.”.

12. In regulation 33 of the said regulations,—

(a) for sub-regulations (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely :—

“(4) On and from the 1st June 2015, privilege leave may be accumulated upto not more than two hundred and

seventy days except where leave has been applied and it has been refused:

Provided that encashment of privilege leave shall be restricted upto a maximum of two hundred and forty days:

Provided further that from the calendar year 2020, an officer shall also be eligible for encashment of privilege leave at the rate of five days for each calendar year at the time of any festival of his choice and an officer who have already completed fifty five years of age as on the 1st January, 2020 and above shall be eligible to encash Privilege Leave at the rate of seven days for each calendar year till his retirement as a one time measure.”:

- (b) after sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be inserted, namely:—

“(5) An officer desiring to avail of privilege leave shall ordinarily give not less than ten days notice of his intention of avail of such leave except for the purpose of leave fare concession.

- (6) Privilege leave taken on sick grounds, when there is no credit in the sick leave account of the officer, shall not be counted as an occasion of availing Privilege Leave.”.

13. In regulation 34 of the said regulations, after sub-regulation (4) the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

“(5) Women officers may avail sick leave for the sickness of their children of eight years and below subject to production of medical certificate.”.

14. For regulation 35 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“35 Additional sick leave :— (1) On and from the 1st January 1989, where an officer has put in a service of twenty-four years, he shall be eligible to additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of twenty-four years subject to a maximum of three months of additional sick leave.

(2) On and from the 1st November, 2017, where an officer has put in a service of thirty years, he shall be eligible for further additional sick leave at the rate of one month for each year of service in excess of thirty years subject to a maximum of three months of additional sick leave:

Provided that the total number of sick leaves shall not exceed seven hundred and twenty days in the entire service of the officer:

Provided further that in case of additional sick leaves availed on or after the 29th June, 1999, commutation of additional leave may be allowed in accordance with sub-regulation (2) of regulation 34.”.

15. For regulation 36 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely:-

“ 36. Maternity leave:— (1) In case of maternity leave,—

- (a) a female employee shall be eligible for maternity leave on substantive pay for a period not exceeding six months on any one occasion and twelve months during the entire period of her service:

Provided that in case of delivery of twins, the period of maternity leave shall be eight months:

Provided further that maternity leave may be availed combining with any other kind of leave except casual leave;

- (b) in case of miscarriage, medical termination of pregnancy or abortion, a female employee may avail maternity leave upto six weeks on the basis of medical certificate or advice of a competent medical practitioner, i.e., a qualified gynecologist. In special or exceptional cases involving medical complications, associated with miscarriage or medical termination of pregnancy or abortion, maternity leave may be availed beyond six weeks, if advised by a competent medical practitioner (qualified gynaecologist) but upto six months only on any one occasion, within the overall limit of twelve months during the entire period of service;
- (c) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hysterectomy upto a maximum of sixty days.

Note: In the case of employees who have availed and exhausted maternity leave of twelve months, leave of fifteen days shall be sanctioned over and above the same, subject to production of medical certificate;

- (d) a childless female employee may avail leave may once during service for legally adopting a child who is below one year of age, for a maximum period of nine months, subject to the following terms and conditions, namely:—

- (i) leave will be granted for adoption of only one child;
 - (ii) the adoption of a child should be through a proper legal process and the employee should produce the adoption-deed to the Bank for sanctioning such leave;
 - (iii) the permanent part-time employees are also eligible for grant of leave for adoption of a child;
 - (iv) the leave shall also be available to biological mother in cases where the child is born through surrogacy;
 - (v) the leave shall be availed within overall entitlement of twelve months during the entire period of service;
- (e) within the overall period of twelve months, leave may also be availed in case of hospitalisation on account of the following gynecological ailments or treatments upto a maximum of thirty days, namely:—
- (i) AUB (Abnormal uterine bleeding);
 - (ii) Ovarian Tumor;
 - (iii) Tubectomy or Tubectomy reversal;
 - (iv) Post-Partum Depression (PPD);
 - (v) Post-Partum Hemorrhage (PPH);
 - (vi) Acute Pelvic Inflammatory Disease (Acute PID);
 - (vii) Dysfunction Uterine Bleeding; Dysfunction (DUB).

- (2) In case of paternity leave, with effect from the 1st June, 2015, male employees with upto two surviving children shall be eligible for fifteen days paternity leave during his wife's confinement and this leave may be combined with any other kind of leave except casual leave:

Provided that the leave may be availed upto fifteen days before or upto six months from the date of delivery of the child:

Provided further that paternity leave as above shall be allowed to a male employee with upto two surviving children for legally adopting a child who is below one year of age.”.

16. For regulation 37 of the said regulations, the following regulation shall be substituted, namely :—

“37. Extra-ordinary leave:— (1) An officer shall be eligible for extraordinary leave on loss of pay for not more than twenty-four months during the entire period of service.

(2) An officer may avail extraordinary leave on any one occasion for a period not exceeding three months and in extreme medical circumstances, he may avail extraordinary leave upto four months on any one occasion.

Note : The employee will not be losing any seniority on account of availing extraordinary leave on medical grounds.”.

17. For regulation 37A of the said regulations, the following regulation be substituted, namely:—

“37A. – Special casual leave and special leave:— (1) With effect from the 1st November, 2020, an officer employee shall be eligible for special casual leave on occasions when the branch where the officer is working or the place where he is residing is affected by curfew, riots, prohibitory orders, natural calamities, floods, etc.

(2) With effect from the 1st November, 2020, a physically or orthopedically handicapped officer shall be eligible for four days special casual leave.

(3) An officer may also be granted special casual leave and any special leave as may be decided by the Board in accordance with the guidelines issued by the Central Government from time to time.”.

18. In regulation 41 of the said regulation, in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

“(a) Halting allowance:— On and from the 1st November, 2020, an officer in the grades or scales set out in column (1) of the Table shall be entitled to ‘per diem’ halting allowance at the corresponding rates set out in column (2) thereof, namely:-

TABLE

Sl. No.	Grades/Scales of officers	Metro Rs.	Major 'A' Class cities Rs.	Area I Rs.	Other Places Rs.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Officers in Scale VI and above	2700	1950	1650	1425
2.	Officers in Scale IV and V	2250	1950	1650	1425
3.	Officers in Scale I, II and III	1950	1650	1425	1200

Provided that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, halting allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation:—For the purpose of computing halting allowance “per diem” shall mean each period of twenty-four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty-four hours, “per diem” shall mean a period of not less than eight hours.”.

19. In regulation 42 of the said regulations, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely:-

“(3) On and from the 1st November, 2020 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc., as specified in the Table below, namely:-

“TABLE

Sl. No.	Grade or Scale	Amount
(1)	(2)	(3)
1.	Top executive and senior management (officers in scale IV and above)	Rs.30,000/-
2.	Middle Management and junior management (officers upto scale III)	Rs.25,000/-”.

20. In regulation 45 of the said regulations, before the note to sub-regulation (4), the following provisos shall be inserted, namely:—

“Provided that with regard to officers covered under Defined Contributory Pension Scheme (New Pension Scheme), the Bank shall make a contribution of fourteen per cent. of pay plus dearness allowance with effect from the 11th November, 2020:

Provided further that the service charges of the Service Provider or Fund Manager of New Pension Scheme shall be borne by the Bank from the financial year 2020-21.”.

21. For the Schedule to the said regulations, the following Schedule shall be substituted, namely: —

“Schedule

(See sub-regulation (2) of regulation 23)

With effect from the 1st day of November, 2017, an officer shall be eligible for the special area allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely:—

TABLE
Special Area Allowance

Sl. No.	AREA	Allowances (Rs.)	
		Pay below Rs.36,001/-	Pay above Rs.36,001/-
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Mizoram		
	(a) Chimpui district and areas beyond 25 kilometers from Lunglei town in Lunglei district;	4000	5200
	b) entire Lunglei district excluding areas beyond 25 kilometers from Lunglei town;	3200	4200
	c) entire Aizawl district	2400	3000
2.	Nagaland	3200	4200
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) North Andaman, Middle Andamans, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	4000	5200
	(b) South Andaman (including Port Blair)	3200	4200
4.	Sikkim	4000	5200
5.	Lakshadweep Islands	4000	5200
6.	Assam	640	800
7.	Meghalaya	640	800
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	3200	4200
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	2400	3000
9.	Manipur	2400	3000
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	4000	5200
	(b) Throughout Arunachal Pradesh other than difficult areas.	3200	4200
11.	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua district: NiabatBani, Lohi, Malhar and Machhodi	4000	5200
	(2) Udhampur district:		
	(i) DuduBasantgarh; Lander BhamagIllaqa, other than those included in Part 2(b).	4000	5200
	(ii) Areas upto Goel from Kamban side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	3200	4200
	(3) Doda district: Illaquas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar tehsil	4000	5200

	(4) Leh district : all places in the district	4000	5200
	(5) Barmulla district: (i) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar sub-division and KeranIllaqua (ii) Matchill	4000 3200	5200 4200
	(6) Poonch and Rajouri district : areas in Poonch and Rajouri district excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two districts	2400	3000
	(7) areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the state government for their own staff.	2400	3000
12.	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba district (i) Pangi tehsil, Bharmour tehsil, Panchayats: Badgaun, Bajol, DeolKugti, Nayagam and Tundah, Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata (ii) Bharmour tehsil, excluding panchayats and villages included in (a) above. (iii) Jhandru panchayat in Bhatiyat tehsil, Churah tehsil, Dalhousie town (including Banikhet proper).	4000 3200 2400	5200 4200 3000
	(2) Kinnaur district: (i) Asrang, Chitkul and HangoKuno/ Charang panchayats, 15/ 20 Area comprising the gram panchayats of ChhotaKhamba, Nathpa and Rupi, Pooh sub-division, excluding the panchayat areas specified above. (ii) entire district other than areas included in (a) above.	4000 3200	5200 4200
	(3) Kullu district: (i) 15/20 area of Nirmand tehsil, comprising the gram panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga (ii) [Outer-Saraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire district excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages Jagat-Khana and Burrow of tehsil Nirmand]	4000 2400	5200 3000
	(4) Lahaul and Spiti district : entire area of Lahaul and Spiti	4000	5200
	(5) Shimla district : (i) 15/20 area of Rampur tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chadi-Branda. (ii) Dora-Kawar tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath tehsil and Munish, Ghorichaibis of Pargana Sarahan. (iii) Chopal tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of ParganaSarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, ParganaBarabis, Kasba Rampur and Ghoris Nog of Pargana Rampur	4000 3200 2400	5200 4200 3000

	of Rampur tehsil, Simla town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).		
	(6) Kangra district: (i) Areas of Bara Bhangal and ChhotaBhangal (ii) Dharamshala town of Kangra district and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town-Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiari, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Shamnagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Shamnagar, Hinwa Project, Shamnagar. Palampur town of Kangra district including HPKVV Campus at Palampur and the following offices located outside its municipal limits but included in Palampur Town – H.P. KrishiVishwavidyalaya Campus, Cattle Development Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division, Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HESEE Division, Ghuggar.	3200 2400	4200 3000
	(7) Mandi district: Chhuhar Valley of Jogindernagar tehsil, Panchayats in thunag tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamlah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil – Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar tehsil – Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura-Kothi, Seri and Shoja.	2400	3000
	(8) Sirmaur district: Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bhargobheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and ThanaKasoga (Nahan Tehsil) and Thansgiri Tract	2400	3000
	(9) Solan district: Mangal panchayat.	2400	3000
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (1) to (9) above.	640	800
13.	Uttar Pradesh: Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi districts	4000	5200
14.	Uttarakhand: Areas under Chamoli, Pithoragarh, Uttarkashi, Rudraprayag and Champavat districts	4000	5200
15.	West Bengal South 24 Pargana district Sunderban areas (south of Dampier Hodge's line), namely, Bhanatush Khali (Rampura), Kumirmari (Bagna), Jhingakhali, Sajnakhali, Gosaba, Amlamathi (Bidya), Canning, Kultali, Piyali, Nalgaraha, Raidighi,	1000	1000".

Bhanchi, PatharPratima, Bhagabatpur, Saptamukhi, Namkhana, Sikarpur, Kakdwip, Sagar, Mousini, Kalinagar, Haroa, Hingalganj, Basanti, kuemari, Kultola, Ghushioghata (Kulti)		
---	--	--

K. RAJESH KUMAR, General Manager

[ADVT.-III/4/Exty./737/2024-25]

Note : The Bank of Maharashtra (Officers') Service Regulations, 1979 were in the Gazette of India, Part III, Section 4. These regulations were subsequently amended *vide* the following notifications: -

Serial number	Notification number	Notification date	Date on which published in the Official Gazette
1.	-----	07.12.1987	26.12.1987
2.	AX-1/ST/OSR/14046/96	05.05.1997	17.05.1997
3.	AX-1/ST/OSR/3169/2001	19.05.2001	16.06.2001
4.	AX-1/ST/OSR/853/2003	11.02.2003	15.03.2003
5.	AX-1/ST/OSR/2053/2006	21.03.2006	07.04.2006
6.	AX-1/ST/OSR/5207/2006	30.05.2008	05.06.2008
7.	AX-1/ST/OSR/1324/2017-18	01.03.2008	14.03.2018
8.	AX1/ST/OSR/1325/2021-22	07.12.2021	14.12.2021

EXPLANATORY MEMORANDUM

These Regulations which have been given retrospective effect are as per the agreed terms and conditions of the Joint Notes signed between the Indian Banks' Association on behalf of member banks on the basis of specific mandate given by the respective banks in this regard and apex level officers' associations of the Banks. Therefore, interests of no person shall be adversely affected by such retrospective effect.